RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : बुधवार, 07 दिसंबर 2022 | वर्ष 04 | अंक 199 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

आर्थर रोड जेल में मिली चरस और संदिग्ध दवा मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

मुंबईः आर्थर रोड जेल में चरस और नशीले कैप्सूल मिले हैं। सूत्रों की मानें तो क्रिसमस और नए साल की पार्टी करने के मकसद से यह अंदर पहुंचाई गई थी। हालांकि पुलिस का इस बारे में कहना है कि इसे बाहर से फेंका गया है। जेल के अंदर जांच व्यवस्था पूरी तरह चौकस है। मुख्य मार्ग से इसे अंदर लाना नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक जेल में तैनात सिपाही अजय धूरी को यहां बैरक नंबर 11 के पास एक पॉलिथिन बैग पड़ा मिला। जांच में उसमें 134 ग्राम चरस और आधा दर्जन से अधिक सफेद रंग की गोलियां बरामद हुई। यह बैग बैरक नंबर 11 के पास पड़ा मिला है। जहां बेहद हाईप्रोफाइल कैदी बंद है। इसी के पास बैरक नंबर 12 खास तौर पर आतंकियों के लिए बनाई गई है। मुंबई हमले में बंद अजमल कसाब को भी यहां रखा गया था। जेल के अंदर चरस मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक यह बैग 30 नवंबर की सुबह करीब 4.30 बजे मिला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बरामद पदार्थ की जांच चल रही है।

...जहां मिला बैग उससे चंद कदमों की दूरी पर बंद यह कैदी

आर्थर रोड के बारे में जानें

जानकारी के मुताबिक वर्ष 1926 में आर्थन रोड जेल बनी थी। ब्रिटिश काल में मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज आर्थर के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। 1994 में इसे केंद्रीय जेल बनाया गया। यह जेल कुल करीब 6 एकड़ में फैली हुई है। इसमें तकरीबन 20 बैरक हैं। यहां कैदियों की क्षमता 804 है। लेकिन अक्सर यहां क्षमता से अधिक कैदी रहते हैं। बैरक नंबर 11 और 12 जिसके पास बैग मिला वह यहां की सबसे संवेदनशील बैरक हैं। यहां हाईप्रोफाइल कैदी रखे जाते हैं। बैरक नंबर 12 को 2008 में मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को रखने के लिए तैयार किया गया था।

वेब सीरीज के नाम पर धोखा... !

वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म की शूटिंग, एक्टर गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई में एक बार फिर अश्लील शूटिंग का मामला सामने आया है. इस मामले में मुंबई के चारकोप पुलिस ने एक एक्टर को गिरफ़्तार किया है. एक्टर पर आरोप है कि वो मॉडल्स को वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने कर बुलाता है और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाता है. इस मामले में पुलिस 3 और आरोपियों की तलाश में है. पुलिस ने बताया है कि गिरफ़्तार एक्टर का नाम अनिरुद्ध प्रसाद जंगडे है. मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि चारकोप इलाके में यह काम एक बिल्डिंग के फ्लैट में चला रहा था, जहां आरोपी अश्लील फिल्म बना रहे थे. 29 वर्षीय मॉडल ने ये मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि वो जॉब के लिए बहुत परेशान थी और हर तरफ लोगों से संपर्क कर एक अच्छे मौके की तलाश में थी.

इसी दौरान शिकायतकर्ता (मॉडल) एक शख़्स से मिली, जिसने दावा किया कि वो वेब सीरीज बनाने वाली एक प्रोडक्शन कंपनी का हिस्सा है और वो उसे अच्छा मौका दिलवा सकता है. शिकायतकर्ता को एक उम्मीद नजर आई और महिला ने उस शख़्स से प्रोडक्शन कंपनी की जानकारी ली और पूछा कि वे लोग उसे क्या काम दे सकते हैं.

अश्लील वीडियो शूट के लिए बनाया दबाव

जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने महिला से कहा कि वे लोग एक वेब सीरिज बना रहे हैं जो कि खास तौर से विदेशी ग्राहकों के लिए है और उस महिला को इस वेब सीरीज में बोल्ड सीन करना पड़ेगा. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह शूट के लिए गई तो उसे एक फ़्लैट में ले जाया गया और उससे धोखे से अश्लील शूट करने को कहा गया. डीसीपी बंसल में बताया कि इस मामले में ऋक्क के बाद चारकोप पुलिस स्टेशन में केस ट्रांसफर हुआ और फिर महिला के बयान के आधार पर क्ढउ की धारा 376 भी जोड़ा गया. महिला ने बताया कि उससे एक कांट्रैक्ट भी साइन कराया गया था.

चार लोगों पर दर्ज है केस...

महिला के साथ हुई इस हरकत के बाद इस बात की शिकायत पुलिस से की. मुंबई पुलिस के जोन 11 के डीसीपी अजय कुमार बंसल ने बताया कि यह घटना 5-6 महीने पुरानी है और महिला ने पहली बार शिकायत भांडुप पुलिस स्टेशन में की थी, जहां चार लोगों के खिलाफ क्ढउ की धारा 354 और क्ळ सेक्शन की संबंधित धाराओं के तहत FIR यास्मीन, अनिरुद्ध प्रसाद जंगडे, अमित पासवान और आदित्य के खिलाफ दर्ज हुई थी.

पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़!

मुंबई : मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब दिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. ये गैंग टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया एप के जरिये पार्ट टाइम जॉब देने के ऑफर वाले मैसेज भेजा करता था और जो लोग इनके झांसे में आ जाते था वो ठगी का शिकार हो जाता था. मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के डीसीपी बालसिंह राजपूत के मुताबिक ये गैंग बड़ी-बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करते थे.

मुंबई में इंदु मिल भूमि पर आंबेडकर स्मारक का काम तेजी से पूरा किया जाएगा : मुख्यमंत्री शिंदे

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि मुंबई के इंदु मिल परिसर में डॉ. बी. आर. आंबेडकर का अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक शानदार स्मारक होगा जिससे दुनिया ईर्ष्या करेगी। आंबेडकर की पुण्यतिथि पर यहां दादर इलाके में उनकी समाधि 'चैत्यभूमि! में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि संविधान निमार्ता से जुड़ी सभी स्मृतियों और इतिहास को संरक्षित रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री के अलावा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के अन्य नेताओं ने भी दादर के शिवाजी पार्क स्थित 'चैत्यभूमि' में आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिंदे ने कहा कि इंदु मिल की जमीन (दादर में चैत्यभूमि के निकट) पर बन रहा डॉ. आंबेडकर का स्मारक एक शानदार दिव्य स्मारक है जिससे ''दुनिया ईर्ष्या करेगी'' और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दादर में आंबेडकर का घर 'राजगृह' एक ''ऐतिहासिक खजाना'' है। उन्होंने कहा कि वहां डॉ. आंबेडकर से संबंधित सभी चीजों को संरक्षित रखा जाएगा और मुंबई में लोअर परेल में डॉ. आंबेडकर के (एक अन्य) स्मारक के स्थान का निरीक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि डॉ. आंबेडकर द्वारा दिया गया समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश विश्व कल्याण का संदेश है। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि महात्मा गांधी और अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों में डॉ. आंबेडकर का नाम सूरज की तरह चमक रहा है।

संपादकीय / लेख

संसद की कार्यवाही...!

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा होने के आसार दिखना कोई नई-अनोखी बात नहीं। अब संसद के प्रत्येक सत्र के पहले ऐसे ही समाचार आते हैं कि सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। कई बार संसद में हंगामा ही अधिक होता है और काम कम। यह सिलसिला तब तक कायम रहेगा, जब तक सत्तापक्ष और विपक्ष यह नहीं समझते कि संसद सार्थक संवाद का मंच है, न कि हल्ला एवं हंगामा करने का अथवा टीवी कैमरों के सामने नारे लिखी तख्तियां लहराने का। संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए, ताकि देश को कोई दिशा मिल सके, लेकिन इसके स्थान पर आरोप-प्रत्यारोप अधिक होता है। कई बार तो इसे लेकर गतिरोध कायम हो जाता है कि पहले किस विषय पर बहस हो और किन नियमों के तहत? कहना कठिन है कि संसद के मानसून सत्र में क्या होगा, लेकिन अच्छा यह होगा कि राजनीतिक दल उन देशों की संसद में होने वाली कार्यवाही को अपना आदर्श बनाएं, जहां प्रत्येक विषय पर धीर-गंभीर बहस होती है। आखिर अपने देश में अमेरिका और ब्रिटेन की संसद की तरह से बहस क्यों नहीं हो सकती? यदि संसद में होने वाली बहस का स्तर ऊंचा उठ सके तो देश सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ-साथ श्रेष्ठ लोकतंत्र की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है।

राजनीतिक दलों को इसका आभास होना चाहिए कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होना ही पर्याप्त नहीं। उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि संसद में होने वाली बहस के गिरते स्तर के चलते उसकी गरिमा में गिरावट आ रही है और आम जनता संसदीय कार्यवाही को लेकर उत्साहित नहीं होती। संसद में प्राय: विपक्ष को यह शिकायत होती है कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। इस शिकायत को दूर करने के लिए संसद का कुछ समय इसके लिए आरक्षित कर देना चाहिए, जिसमें विपक्षी दल जिस भी विषय पर चाहें, अपनी बात रख सकें।

इस पर हर्ज नहीं कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने यह संकेत दिया कि संसद के मौजूदा सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विषय उसकी प्राथमिकता में होंगे। जहां सत्तापक्ष को इन विषयों पर विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, वहीं विपक्ष को भी यह आभास कराना चाहिए कि उसका उद्देश्य अपने सवालों के जवाब पाना है, न कि हंगामा कर सदन की कार्यवाही ठप करना। सत्तापक्ष को इसके लिए भी तत्पर रहना चाहिए कि संसद के इस सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित हों। ये विधेयक व्यापक विचार-विमर्श के साथ पारित होने चाहिए। जब कभी आवश्यक विधेयक संसद में अटके रह जाते हैं तो इससे कुल मिलाकर देश को नुकसान होता है।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

BMC के लिए कमाई का जरिया बनने जा रही प्रयोगशाला !

मुंबई : अभी हाल ही में हाईटेक , बनाई गई बीएमसी की प्रयोगशाला अब बीएमसी के लिए कमाई का जरिया बनने जा रही है। बीएमसी विजिलेंस विभाग ने एमएमआर की सभी महानगर पालिकाओं को सामग्री की जांच करने बीएमसी प्रयोगशाला में कराने के लिए पत्र लिखा है। इससे उन महानगर पालिकाओं का समय के साथ खर्च भी बचेगा। साथ ही बीएमसी की भी आय बढ़ेगी। मुंबई में बीएमसी कई नए विकास कार्यों के साथ-साथ मरम्मत और रखरखाव के कार्य भी करती है। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले सामग्री की जांच करने के लिए बीएमसी ने 1958 में प्रयोगशाला बनाया था। जहां मुख्य अभियंता (विजिलेंस) विभाग की देखरेख में कार्यों प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण किया जाता है।

बीएमसी सड़कें, पुल, भवन निर्माण, भवन रखरखाव/मरम्मत, मुंबई सीवेज परियोजना, सीवेज संचालन, जल अभियंता, जल आपूर्ति परियोजना, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज लाइन, अस्पताल, पार्क आदि में होने वाली सामग्री की जांच यहां की जाती है। अब इस प्रयोगशाला को हाईटेक किया गया है। विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे सीमेंट, मिट्टी/लोहा, बजरी, ईंट, बालू, लकड़ी, लादी, तारकोल, डामर, कंक्रीट आदि निर्माण सामग्री के नमूनों की जांच की जाती है।

मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बन गई

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला और प्रत्यायन बोर्ड ने बीएमसी की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण कर राष्ट्रीय रेटिंग का दर्जे का प्रमाण पत्र दिया है। इसलिए राष्ट्रीय परीक्षण और मात्रात्मक प्रयोगशाला (एनएबीएल) द्वारा प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बन गई है। बीएमसी के ज्वाइंट कमिश्नर और विजिलेंस विभाग के प्रमुख अजित कुंभार ने बताया कि बीएमसी प्रयोगशाला में कंक्रीट गुणवत्ता निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए दो अत्याधुनिक नियंत्रित और स्वचालित मशीनें लगाई गई हैं। चूंकि ये मशीनें आटोमेटिक हैं, इसलिए परीक्षण की गति में वृद्धि हुई है। कम से कम समय में सटीक जांच रिपोर्ट मिल जाती है। जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी बढ़ गई है। इस प्रकार, निकट भविष्य में कई उन्नत मशीनरी, उपकरण और प्रौद्योगिकियां परीक्षण कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी और 150 से अधिक निर्माण सामग्री की जांच के लिए तैयार किया गया है। अजित कुंभार ने बताया कि बीएमसी प्रशासन अन्य शासकीय, अर्धशासकीय (म्हाडा, सिडको, पीडब्ल्यूडी आदि) के साथ-साथ निजी बिल्डरों, ठेकेदारों और संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों की सामग्री का परीक्षण बीएमसी प्रयोगशाला में करने का इच्छुक है। इससे बीएमसी की आय भी बढ़ेगी।

ऑनलाइन मिलेगी रिपोर्ट

कुंभारे ने कहा कि सामग्री का परीक्षण नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उसके लिए एक मोबाइल एप की व्यवस्था की जा रही है, प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस, चालान, परीक्षण रिपोर्ट आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे संबंधित को मोबाइल या ई-मेल पर कम से कम समय में सही रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। बीएमसी की प्रयोगशाला हाईटेक होने के बाद अब प्रयोगशाला को राष्ट्रीय मानक भी प्राप्त हो गया है।

खाद्य अधिकारी बनकर न्यापारियों से करते थे ठगी

पुलिस ने धरा, 70 से ज्यादा मामलों में आया नाम

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर व्यापारियों से ठगी के आरोपी जालसाजों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी जालसाजों के एक गिरोह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने एक और रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट के लोग वेब सीरीज के बहाने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें विभिन्न साइटों पर अपलोड करते थे।

खाद्य अधिकारी बनकर ठगी करने वाले जालसाज गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जालसाजी करने वाले आरोपियों की पहचान कांदिवली के सिंह एस्टेट ठाकुर गांव निवासी 25 वर्षीय धर्मेश प्रसाद शिंदे और चारकोप निवासी 35 वर्षीय अविनाश गायकवाड़ के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) स्मिता पाटिल ने कहा कि दोनों आरोपियों ने नकली खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर व्यापारियों से जबरन वसूली की और शहर में 70 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान, दोनो जालसाजों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में व्यापारियों पर अनाज की गुणवत्ता में कमी के आरोप लगाते हुए कार्रवाई नहीं करने के लिए मोटी रकम वसूली। उन्होंने बताया कि एक दुकानदार ने इन दोनों की शिकायत की थी। जिसके आधार पर मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने एक जाल बिछाया और दो आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारते थे और उनके सामान में गुणवत्ता की कमी का आरोप लगाते थे। जिसके बाद कार्रवाई नहीं करने के लिए मोटी रकम वसूलते थे।

नवी मुंबई में कचरा संग्राहकों को मिला आकर्षक जैकेट

नवी मुंबई : स्वच्छता के मामले में देश में प्रथम स्थान हासिल करने का प्रयास नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत महानगरपालिका द्वारा नागरिकों में स्वच्छता और कचरे के वर्गीकरण के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिसे और प्रभावशाली बनाने के लिए महानगरपालिका द्वारा सफाई विभाग से जुड़े 720 कर्मियों को आकर्षक जैकेट वितरित किया गया। जिस पर स्वच्छता और कचरे के वर्गीकरण के बारे में संदेश लिखा गया है।

गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगरपालिका के क्षेत्र में हर दिन 760 मैट्रिक टन निकलता है। जिसे दो प्रकार के वर्गों में अलग किया जाता है। एक वर्ग में सूखे कचरे को रखा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग में गीले कचरे को। महानगरपालिका द्वारा गीले कचरे से खाद तैयार की जाती है। जिसका उपयोग महानगरपालिका के बगीचे में किया जाता है। महानगरपालिका क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को यह अति आवश्यक है कि वह अपने घर में उत्पन्न होने वाले स्थान अर्थात घर में ही कूड़ा अलग-अलग रखकर कचरा उठाने वाले महानगरपालिका कर्मियों को दे। महानगरपालिका द्वारा वितरित किए गए उक्त जैकेट के सामने की ओर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के प्रतीक नवी मुंबई महानगरपालिका और स्वच्छता के दो रंग हर गीला और नीला सूखा का प्रतीक प्रदर्शित है। इसी तरह जैकेट के निचले हिस्से पर गीला और सूखा कचरे के कार्टून के चित्र छपवाए गए हैं, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग दिया जाना चाहिए और डिब्बे का रंग हरा और नीला होना चाहिए।

स्कूली छात्र गणित के खराब अंकों से परेशान

मुंबईः पूरे मुंबई में माध्यमिक कक्षाओं के छात्र परेशान रहते हैं क्योंकि दो साल के ऑनलाइन सत्र के बाद गणित विषय में उनका प्रदर्शन खराब हो गया है। भांडुप के कक्षा 8 के छात्र रिहान शाह ने कहा, ''गणित जैसे विषय को पढ़ाने और सीखने की जरूरत तब होती है जब शिक्षक और छात्र शारीरिक कक्षा के लिए बैठते हैं, न कि ऑनलाइन।''

छात्र अपने गणित के अंकों को गिराए जाने के बारे में विवरण देते हैं

छात्र बीजगणित विषयों की तुलना में अपनी ज्यामिति अवधारणाओं के अंकों से अधिक असंतुष्ट रहते हैं। उनके अनुसार, ज्यामिति में राउंडर, प्रोट्रैक्टर और अन्य उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है; हालाँकि, जब इसे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो अवधारणाओं को समझना मुश्किल हो जाता है। शहर के छात्रों ने रोते हुए कहा कि जब व्याख्यान ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे थे तो उन्हें गणित की आवश्यक अवधारणाएँ समझ नहीं आ रही थीं।

''मैं शुरू से ही गणित में एक औसत छात्र रहा हूँ। इसके अलावा, शिक्षक कभी-कभी ऑनलाइन व्याख्यान के दौरान मुझे संतोषजनक ढंग से अवधारणाओं को समझाने में सक्षम नहीं होते थे, ''वाशी के एक छात्र आफताब शेख ने कहा।

शेख ने कहा कि उनके स्कूल के ऑफलाइन शुरू होने के बाद वह गणित में 50-55% से अधिक अंक नहीं ला पा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन व्याख्यान से पहले 65-70% से नीचे नहीं जाता था। कांदीवली के एक छात्र अरमान चौहान ने इस विषय के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महामारी की चपेट में आने से पहले वह कभी भी गणित में ए* ग्रेड से नीचे स्कोर नहीं करते थे। अब, उन्होंने कहा, ''बी अधिकतम ग्रेड है जिसे मैंने प्राप्त किया है, और मैं दो साल के ऑनलाइन व्याख्यानों को दोष देता हूं।''

चौहान ने कहा कि अपने शुरूआती स्कोर पर वापस जाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करने के बावजूद, ''यह लगभग असंभव लगता है।'' छात्र ने आगे उल्लेख किया कि उसके शिक्षक ने जूम सत्र में कुछ विषयों को यह कहते हुए पढ़ाना छोड़ दिया था कि उन विषयों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता है।

अभिभावक स्कूलों को दोष देते हैं

माता-पिता भी इस पर नाराज हैं और

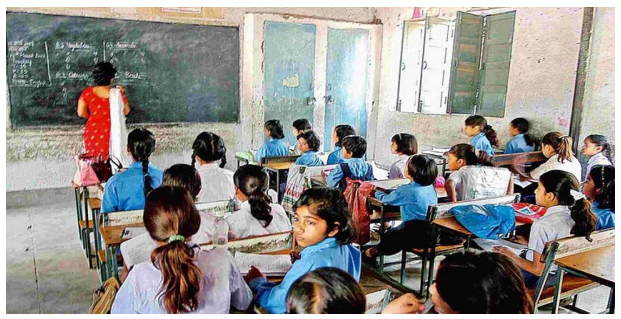

स्कूलों से इस विषय में अपने बच्चों के स्कोर में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों को पटरी पर लाने से ज्यादा शिक्षकों का काम है। माता-पिता के अनुसार, एक बार ऑफलाइन स्कूल शुरू होने के बाद शिक्षकों को छात्रों के लिए क्रैश कोर्स आयोजित करना चाहिए था, जिसे समझना उनके लिए कठिन था।

घाटकोपर की एक माता-पिता कविता पारिख ने कहा, उनके बेटे रुद्र के अंक ऑनलाइन सत्रों के कारण अंक तक नहीं आए हैं। उसने कहा, ''रुद्र ने ऑनलाइन सत्र के दौरान ध्यान नहीं दिया और ऑनलाइन गणित सीखना उसके लिए उबाऊ हो गया। उसने पर्याप्त गणित का अभ्यास भी नहीं किया था क्योंकि ऑनलाइन होमवर्क जमा करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी।''

फ्री प्रेस जर्नल से बात करने वाले माता-पिता के अनुसार, छात्रों ने अपना अधिकांश खाली समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टीवी शो और फिल्में देखने में बिताया और गणित पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जो कि महत्वपूर्ण है और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दैनिक अभ्यास की आवश्यकता है।

अंधेरी के एक स्कूल में पढ़ने वाले अमृत के माता-पिता गुरमीत सिंह ने कहा, ''मेरी बेटी, अमृत, जो ऑनलाइन कक्षाओं से पहले गणित में शानदार थी, का गणित में 60% का उच्चतम स्कोर है।'' उन्होंने कहा कि न केवल गणित में, बल्कि अमृत के स्कूल में विभिन्न विषयों के शिक्षकों ने महामारी के मद्देनजर कई विषयों को छोड़ दिया था.

अभिभावकों ने लॉकडाउन वाले हिस्से को कवर करने के लिए स्कूल अधिकारियों से गणित के लिए अतिरिक्त व्याख्यान देने का अनुरोध करने का भी उल्लेख किया है, लेकिन कुछ स्कूलों ने अभी भी इस विचार को लागू नहीं किया है। माहिम के एक अभिभावक अंकुर देशपांडे ने कहा कि उनकी बेटी के स्कूल ने गणित में छात्रों की मदद के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ''मेरी बेटी के लिए मुख्य मुद्दा यह था कि लॉकडाउन से पहले उसे पढ़ाने वाला शिक्षक वही नहीं था जो ऑनलाइन सत्र के दौरान पढ़ाता था। छात्रों को नई शिक्षण पद्धति के अनुकूल होने में बहुत समय लगा, ''अंकुर ने कहा।

प्राचार्यों और शिक्षकों का कहना है कि अंकों में गिरावट अपेक्षित थी

शहर भर के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षण के कारण स्कोर गिरने की उम्मीद की थी। वे इस बात से सहमत हैं कि कई विषय ऑनलाइन पढ़ाए जाने के लिए नहीं थे, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के कारण वे असहाय थे।

डॉ. कविता अग्रवाल, प्राचार्य, डी. जी. खेतान इंटरनेशनल स्कूल, मलाड ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं की शुरूआत के साथ, गणित अवधारणा-ग्रा'ता की तुलना में रट्टा सीखने का अधिक हो गया है। ''गणित एक ऐसा विषय है जिसे भावात्मक रूप से पढ़ाने की आवश्यकता है। इसे आदर्श रूप से प्रॉप्स के पर्याप्त उपयोग के साथ और तार्किक सोच को साबित करके सिखाया जाना चाहिए,'' उसने कहा।

प्रधानाचार्यों ने कुछ एआई उपकरणों की भागीदारी का भी उल्लेख किया जो छात्रों को खुद से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते थे और उन्हें बताते थे कि वे वास्तव में कुछ कठिन विषयों के साथ कहां खड़े हैं। एआई अनुप्रयोगों ने समस्याओं को हल करते समय छात्रों की गति को बेहतर बनाने में मदद की और कठिन विषयों में उनकी निरंतरता को बनाए रखा।

जेबीसीएन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर के प्रधानाचार्य सुमित दरगन ने कहा, ''गणित के अंकों के साथ स्थिति इतनी खराब थी कि अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और ऑफलाइन व्याख्यानों की आवश्यक संख्या से अधिक होने के बावजूद पाठ्यक्रम को कम करना पड़ा।'' एआई टूल्स के बारे में पूछने पर, उन्होंने कहा कि वे फायदेमंद थे क्योंकि वे छात्रों को फंसने के बजाय प्रतिस्पर्धी होने देते हैं।

महाराष्ट्र टूटा तो सब कुछ राख हो जाएगा, आव्हाड की चेतावनी!

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चांगलाच पेटला असून आज याला हिंसक वळण मिळालं आहे. कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या बसची तोडफोड करण्यात आली. या घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांना गंभीर इशारा दिला आहे. महाराष्ट्राचे तुकडे होणार असतील तर सर्वकाही राख होईल, असं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. चैत्यभूमी इथं महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी आलेले असताना ते मीडियाशी बोलत होते.

आव्हाड ने कहा, ''अगर आप हमारी बसों को तोड़ते हैं, तो क्या हम आपकी बसों को नहीं तोड़ सकते? यह मत सोचिए कि हमारे हाथों में चूड़ियां हैं। अगर आप पूरे कर्नाटक में मराठी लोगों का प्रतिशत देखें तो यहां 25 फीसदी, 100 फीसदी हैं। बंगलौर से ज्यादा लोग मुंबई में हैं। हम उनका ख्याल रखते हैं। हमारा मराठी आदमी ही उनका इडली डोसा खाने जाता है। तो क्या बोम्मई इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं? महाराष्ट्र को अस्थिर कर रहा है। यह महाराष्ट्र के हित में नहीं है। तो अगर मेरी तरह किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि महाराष्ट्र पांच टुकड़ों में बंटने वाला है, तो सब कुछ राख हो जाएगा।'

मुझे लगता है कि पीएम को वास्तव में बोम्मई को शांत रहने के लिए कहना चाहिए था। इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। यह विवाद आज का नहीं 1946 से शुरू हुआ था. किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कैसे कर सकता है जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। अवध ने यह भी कहा कि जब मामला चल रहा हो तो आपका इस तरह का बयान देना गलत है।

यह दिखाना सरकार का काम है कि महाराष्ट्र का हर मराठी व्यक्ति वहां का है। बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान से ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा पर प्रांत गठन 1956 में किया गया था। इसके अनुसार महाराष्ट्र में पहला आंदोलन मराठी साहित्य सम्मेलन में हुआ। इसकी अध्यक्षता जतरम माडगुलकर ने की। उन्होंने संकल्प लिया था कि महाराष्ट्र को बिदरी, भाल्की, कारवार, बेलगाम और मुंबई के साथ मिलाना चाहिए। इसके लिए कई लोगों की जान गई लेकिन महाराष्ट्र को सिर्फ मुंबई मिली। बेलगाम के लोग तब से लड़ रहे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। सरकार का यह कहना जरूरी है कि सभी मराठी लोग उनके साथ खड़े हैं, उन्होंने शिंदे-फडणवीस सरकार पर भी निशाना साधा.

शरद पवार ने दिया 24 घंटे का अल्टिमेटम

पत्थरबाजी के बाद कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा विवाद हुआ तल्ख...

मुंबईः महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी के हीरेबागवाड़ी में मंगलवार सुबह महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ट्रक पर हमला हुआ था जिसके बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। विवाद बढ़ते देख महाराष्ट्र ने कर्नाटक के लिए अपनी बस सेवाओं को फिलहाल रोक दिया है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को दूसरे राजनीतिक दलों का भी साथ मिल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले में कड़े तेवर दिखाए हैं। शरद पवार ने कहा कि अगले 24 घंटे में ऐसी घटनाएं रुक जानी चाहिए।

शरद पवार ने कहा कि 'यह कई सालों का विषय है। इसलिए जब भी कभी सीमा विवाद मामले पर वहां कुछ भी घटता है, तो मुझे कॉल आती है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोग मुझे कई मेसेज कर रहे हैं। पवार ने आगे कहा कि डेप्युटी सीएम ने वहां के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की लेकिन

इससे कुछ होनेवाला नहीं है, सीमा पर आने-जाने वाले वाहनों को लेकर एक बड़ी परेशानी बनती दिख रही है, जिस तरह से वहां हमला किया गया और घटना घटी, यह बेहद गंभीर है।'

'मामला बिगड़ा तो जिम्मेदारी कर्नाटक की'

पवार ने कहा कि 'आनेवाले 24 घंटे के अंदर अगर कर्नाटक सीमा विवाद मामला शांत नहीं होता, तो उसकी पूरी जवाबदेही कर्नाटक और केंद्र सरकार को अपने ऊपर लेनी होगी।' शरद पवार ने कहा, '24 घंटे हम देखेंगे कि कर्नाटक की भूमिका क्या है? परिस्थिति बिगड़ी तो जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी।' शरद पवार ने कहा कि 'यह सीमा विवाद अगर नहीं सुलझा तो देश की एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पवार ने कहा है कि जिस तरह से घटना हो रही है, उसे देखकर यही कहूंगा कि महाराष्ट्र के लोगों का संयम न देखें।'

पवार की शिंदे को सलाह

एनसीपी प्रमुख ने कहा, 'बेलगावी और आसपास के जो भी गांव है, एक प्रकार से वहां दहशत निर्माण की जा रही है, वहां के नागरिक चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था की जाए, लेकिन जिस तरह से स्थिति बन रही है, तो हम जैसे लोगों को आगे आना होगा।' एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सभी सांसदों से अपील की है कि वे एकजुट होकर संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएं।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार, 07 दिसंबर 2022

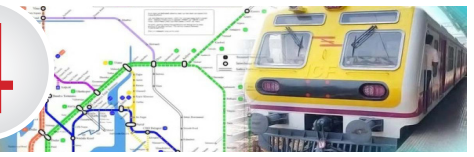

महाराष्ट्र में है पूरी तरह असंवैधानिक सरकार:

उद्धव गुट, उच्चतम न्यायालय में 13 जनवरी को सुनवाई...!

नयी दिल्ली : उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के धड़े ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि महाराष्ट्र में ''पूरी तरह असंवैधानिक सरकार'' काम कर रही है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रकरण से संबंधित याचिकाओं पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी क्योंकि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के लिए अगले सप्ताह वाला सप्ताह होगा। पांच न्यायाधीशों के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ में बैठना संभव नहीं होगा। हम मामले पर 13 जनवरी, 2023 को विचार करेंगे।'' शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के यह कहने के बाद की कि ''इस मामले में कुछ तात्कालिकता है क्योंकि राज्य में पूरी तरह से असंवैधानिक सरकार चल रही है।'' पीठ ने कहा कि वह 13 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने एक नवंबर को कहा था कि वह ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा महाराष्ट्र राजनीतिक प्रकरण पर दायर याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी, जब उसके द्वारा कुछ निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों को अपने लिखित अभिवेदन दाखिल करने और संविधान पीठ द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों पर एक संयुक्त संकलन दाखिल करने को कहा था।

बीएमसी चुनाव से पहले कर्ज के जरिए फेरीवालों तक पहुंच बना रही BJP

दस हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक का मिलेगा कर्ज, फिर मुंबई में हॉकर्स पॉलिसी पर खामोशी क्यों?

मुंबई : मुंबई में फेरीवालों के लिए नीति कब लागू होगी, कितने फेरीवालों को फायदा मिलेगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वहीं मुंबई में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2 लाख फेरीवालों को कर्ज देने की योजना है। सरकार और बीएमसी प्रशासन का मानना है कि इससे फेरीवालों को अपना रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी इसके जरिए लाखों फेरीवालों तक पहुंचने की योजना बना रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा कि मुंबई में एक महीने के भीतर 1 लाख फेरीवालों को इस योजना के तहत कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि 8 साल से लटकी हॉकर्स पॉलिसी मुंबई में कब लागू होगी, इस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कराड ने कहा कि वह दूसरा विषय है। वहीं

बीजेपी नेता अपने-अपने क्षेत्र में कैंप लगा कर फेरीवालों को कर्ज दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।

लिया जाएगा चार प्रतिशत ब्याज

मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कराड ने कहा कि फेरीवालों को इस योजना के तहत 10000 रुपये से लेकर 50000 रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। फेरीवाले यदि नियमित रूप से ऋण अदायगी करते हैं तो यह ऋण भविष्य में 10 लाख तक लिया जा सकता है। योजना के तहत फेरीवालों से 4 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा।

आठ साल में करीब दो गुने हुए फेरीवाले

खास बात यह है कि करीब आठ साल पहले किए गए सर्वे में 1.28 लाख फेरीवाले मिले थे। उसके बाद बीएमसी ने मुंबई में फेरीवालों का नया सर्वे नहीं कराया है, लेकिन दो लाख फेरीवालों को कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। कराड ने कहा कि हॉकर्स को कर्ज दिलाने में बीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश है कि फेरीवालों को कर्ज वितरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हो। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी प्रयास कर रहे हैं कि पीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहें।

मुंबई के पड़ोसी फेरीवाले भी शामिल

मुंबई में फेरीवालों की संख्या को देखते हुए, हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हों। इस प्रक्रिया में अब तक 60 हजार फेरीवाले शामिल हो चुके हैं। एक महीने के भीतर इस संख्या में एक लाख और फेरीवाले जुड़ जाएंगे। कराड ने कहा कि इस योजना में मुंबई के फल और सब्जी विक्रेता से लेकर मछली विक्रेता तक हर कोई भाग ले सकता है। मुंबई से सटी वसई-विरार, ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली और भिवंडी के लिए 50,000 फेरीवालों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

संपत्ति कर विभाग ने वसूले 515 करोड़, पिछले साल से 150 करोड़ ज्यादा

ठाणे : कोरोना संक्रमण काल के दो साल के लंबे अंतराल के बाद आज भी महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है। लेकिन इन सभी के बीच महानगरपालिका संपत्ति कर विभाग महानगरपालिका को आर्थिक बल प्रदान करता नजर आ रहा है। संपत्ति कर विभाग ने अब तक कुल 515 करोड़ रुपए की वसूली की है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में डेढ़ सौ करोड़ रुपए अधिक है। साथ ही शुरू आर्थिक वर्ष का 68 फीसदी वसूली पूरा करने में टैक्स विभाग सफल रहा।

वैश्विक कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और फिर लोगों द्वारा समय पर टैक्स न भरे जाने के कारण ठाणे महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और कई विकास कार्य भी रुक पड़े थे। महानगरपालिका प्रशासन के ऊपर आज भी करीब 2700 का दायित्व है। अर्थात इतनी रकम महानगरपालिका को ठेकेदाराओं और अन्य संबंधित संस्थाओं को देना है। महानगरपालिका की तिजोरी में पैसा न होने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में आज भी विकास कार्य शुरू है। जिसका मुख्य श्रेय संपत्ति कर विभाग को जाता है।

वर्ष 2022-23 के चालु आर्थिक वर्ष में महानगरपालिका के टैक्स विभाग को 700 करोड़ के आसपास का लक्ष्य दिया गया है। मनपा टैक्स विभाग ने अप्रैल से लेकर अब तक 515 करोड़ रूपए की वसुली करने में सफल रही है। इतना ही नहीं 500 वर्ग फुट के घरों की संपत्ति कर माफी के बाद भी इस प्रकार विक्रम वसूली से अब महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टैक्स विभाग को छोड़ दिया जाए तो महानगरपालिका के अन्य विभाग जैसे पानी बिल वसूली, शहर विकास विभाग, विज्ञापन विभाग, इस्टेट विभाग और अतिक्रमण विभाग की तरफ से होने वाली वसूली बहुत ही काम है, जोकि महानगरपालिका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

मुंबई में 8 साल की बच्ची को जबरन किस करने वाले दोषी को 5 साल की जेल

मुंबई : मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को आठ साल की बच्ची के अपहरण और उसका यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2015 का बताया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 10 जुलाई 2015 को दोपहर करीब दो बजे बच्ची की मां ने उसे (पीड़िता) साबुन खरीदने के लिए भेजा था। कुछ समय बाद वह दौड़ती हुई और मदद के लिए चिल्लाते हुए घर लौटी। उसने अपनी माँ को बताया कि एक आदमी उसे पड़ोस की इमारत में यह कहकर ले गया कि उसके पिता उसके घर में हैं और उसके लिए एक ड्रेस लाये है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसे चूमने की कोशिश की।

अदालत में गवाही देने वाले गवाहों में नाबालिग भी शामिल थी। पीड़िता ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह आरोपी के चंगुल से किसी तरह बच निकलने में सफल रही, और उसने एक महिला को इसके बारे में बताया। महिला ने पीड़िता की मां को बताया कि जब वह बिल्डिंग में पहुंची तो उन्होंने आरोपी को वहीं खड़ा पाया। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी को पुलिस स्टेशन लाया गया। बच्ची ने कोर्ट में आरोपी की शिनाख्त की है। आरोपी अगस्त 2015 से जमानत पर बाहर है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com

www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani